

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषय: राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में की गयी है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधानित है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र के प्रयोजन से परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में अर्जित भूमि और सम्पत्ति को संयोजित (Club) करते हुए सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) निर्गत किये जायेंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साथ-साथ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का भी सत्यापन कराये जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रखी जायेगी। यदि आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र जाली/गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

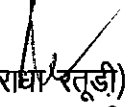
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित पद के विज्ञापन में आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

naresh

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(राधा रतूडी)

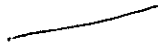
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: (1)/XXX(2)/2019-30(1)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,


(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

Handwritten signature



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 मार्च, 2019 ई0

फाल्गुन 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 64/XXXVI (3)/2019/19(1)/2019

देहरादून, 07 मार्च, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019’ पर दिनांक 05 मार्च, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 07, वर्ष, 2019 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2019)

"भारत का संविधान" का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से संविधान का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) में विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभिप्रेत है;
- (ग) "परिवार" से आरक्षण चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहनों के साथ-साथ उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित हैं, अभिप्रेत हैं;
- (घ) "लोक सेवाओं और पदों" से राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवा और पद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें और पद भी सम्मिलित हैं :
 - (एक) स्थानीय प्राधिकारी,
 - (दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (अ) जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(ङ) "भर्ती का वर्ष" से किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, अभिप्रेत है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण

3. (1) लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, दस प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा।

(2) (क) लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में विहित हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी;

परन्तु यह कि जिनके पास या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

- (3) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, की जायेगी।
- (4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।
- (5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

अधिनियम के
अनुपालन के
लिए
उत्तरदायित्व
और शक्ति

4. (1)

राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2)

राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

शास्ति

5. (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6. यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) उल्लिखित वर्गों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकेगी और ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

प्रमाण-पत्र

7. इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा;

परन्तु यह कि आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक नियमों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जायेगा।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति 8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण 9.

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना 10.

धारा 3 की उपधारा (3), धारा 4 और धारा 8 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे उत्तराखण्ड के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

11. (1)

इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती;

(एक) जहाँ केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

- (2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 तथा भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- नियम बनाने की शक्ति 12. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- निरसन और व्यावृत्ति 13. (1) उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019

Dated Dehradun, March 07, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019' (Act No. 07 of 2019).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 March, 2019.

The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019

(Uttarakhand Act No. 07 Year 2019)

An

Act

to determine the procedure for Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) under the Article 15(6) and Article 16(6) of the Constitution of India;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called 'The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

- (2) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act,:-

(a) "Appointing Authority" in relation to public services and posts means the Authority empowered to make appointment to such services and posts;

(b) "Economically weaker Sections" means economically weaker sections specified in Article 15(6) and Article 16(6) of the Constitution;

(c) "Family" means person demanding reservation, their husband/wife and children of less than 18 years of age along with his parents, his siblings less than of 18 years of age, as well as it includes his husband/ wife and children of less than 18 years of age;

(d) "Public Services and Posts" means the services and posts in connection with the affairs of the state and includes following posts and services:-

(i) Local Authority;

(ii) Clause (a) of Section 2 of the Uttarakhand Co-operative Committee Act, 2003 in which not less than 51 percent of share capital of Holding Share Committee by the State Government;

(iii) Any board or any corporation or any legal body established by the any central or Uttarakhand State Act which is under the owner ship or control of the State Government or Government company defined in the Company Act, 2013, in which not less than 51 percent paid up share capital by the state;

(iv) any educational institute under ownership and control of the State Government or which receives grants in aid from the State Government including a university established by or under Act of Uttarakhand State, except any institute established and administered by minority section specified in clause (1) of article 13 of the Constitution of India;

(e) "Year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of 12 months commencing on first of July of a year, within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated;

Reservation in
favour of
economically
weaker sections

3. (1) In public services and posts, on the order of direct recruitment vacancies to be recruited in accordance with the roster specified in sub-section (4), 10 percent shall be reserved in the favour of concerned persons of the economically weaker sections.
- (2) (a) In public services and posts, the reservation in favour of economically weaker sections shall be given to such permanent residents of the State of Uttarakhand, which are not included in the existing reservations schemes for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Socially and Educationally Backward Classes.
- (b) The persons of such economically weaker sections are identified for the reservation as economically weaker section, whose gross annual income of family, from all sources is less than ₹ 8.00 lakh (₹ eight lakh). Family income includes income received from all sources namely- salary, agriculture, profession, business etc. The said income shall be income of the previous financial year, from the year of application, by the beneficiary;

Provided that the person or their family possess any property, from the following properties, shall not be eligible for the reservation as economically weaker sections:-

- (i) 5 acre of agricultural land or above; or

- (ii) residential building of 1000 sq. feet or above; or
 - (iii) residential plot of 100 sq. yards or above in notified municipalities; or
 - (iv) residential plot of 200 sq. yards or above in areas other than the notified municipalities.
- (3) If, in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, the special recruitment shall be made for filling such vacancy from amongst the persons belonging to that category.
- (4) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by notified order issue a roster which shall continuously apply, till it is exhausted.
- (5) If a person belonging to economically weaker sections as mentioned in sub-section (1), get selected on the basis on merit in an open completion with general candidates, he/she shall not be adjusted against the vacancies, reserved for such category, under sub-section (1).

**Responsibility
and power for
compliance of
Act**

4. (1) The State Government may by notified order entrust the appointing authority or any officer or employee with responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.
- (2) The State Government may in the like manner vest the appointing authority or officer referred in sub section (1) with such power or authority as may be necessary for effective discharging the responsibility entrusted to him under sub section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of Section 4, willfully acts in manner to contravene or defeat the purposes of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to ₹ 20000 or both;
- (2) No court shall take the cognizance of any offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by order ;

(3) An offence punishable under sub section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of First class and provision of sub section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call records

6. If it come to the notice of the State Government that any person of category mentioned in sub section (1) of Section 3 is adversely effected due to compliance with order of Government for its purposes or provision of this Act or rules made under it than it can demand such records and shall take action which it deems necessary.

Certificate

7. For the purposes of reservation provided under this Act, certificate of economically weaker section shall be issued by such officer or authority and in such manner and form as the State Government shall, by order, provide ;

Provided that certificate regarding income and property shall be issued by officer not below the rank of Tahsildar, following the proper procedure after carefully verifying the all relevant rules,.

Power to remove difficulties

8. (1) If any difficulties arises in giving effect to the provision of this Act, State Government may by notified order shall make such provisions not inconsistent with the provision of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

Protection of action taken in good faith

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against State Government or any person, for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or rules made thereunder.

Laying of orders etc.

10. Every order made under sub-section (3) of Section 3, Section 4 and Section 8 shall be laid, as soon as may be, before State Legislative Assembly and the provisions of sub section (1) of Section 23(a) of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in Uttarakhand) shall apply as they apply in respect of the rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

Savings

11. (1) The provisions of this Act shall not be apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement;

Explanation- For the purpose of this sub section selection process shall be deemed to be initiated where, under relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of :-

(i) written exam or interview only, the written test or interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written exam and interview, the written test has started.

- (2) The provisions of this Act shall not be apply to the appointment, to be made under Uttar Pradesh Recruitment of Dependant of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 and The Dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services Employment Rules, 2018.

Power to make rules

12. The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal Savings

and

13. (1) The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance specified in sub section (1) shall be deemed to have been done under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

उद्देश्य व कारणों का कथन

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का लोक सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व अन्य वर्गों की तुलना में अनुपातिक रूप से पर्याप्त नहीं है, अतः उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये लोक सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराने हेतु विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2019 का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।